

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371

वर्ष: 47

संख्या: 177

प्रभात

बीकानेर, सोमवार 19 जनवरी, 2026

डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

तृणमूल सरकार का घुसपैठियों को संरक्षण, सुरक्षा से खिलवाड़ है- मोदी

प्रधानमंत्री ने हुगली में विशाल आमसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को कठघरे में खड़ा किया

कोलकाता/नयी दिल्ली, 18 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुणमूल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देकर बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ये घुसपैटिए उनके लिये पक्का वोट बैंक हैं। मोदी ने रविवार को हुगली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तुणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में अवैध घुसपैठ, कानून-व्यवस्था की बद्दहाली, भ्रष्टाचार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और इसी सोच के साथ केन्द्र सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने

- प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, कानून व्यवस्था की बद्दहाली, भ्रष्टाचार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे जिम्मेदार ठहराया।

- प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद पिछले 100 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है, जब 24 घंटे के भीतर बंगाल की रेल संरचना को लेकर इतने बड़े फैसले लिए गये हों।

कहा “कल मैं मालदा में था और आज हुगली में आप सभी के बीच हूं। पिछले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के रेल और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ऐतिहासिक रहे हैं।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगुर की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग 15 साल के महा-जंगलराज से मुक्ति चाहते हैं। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

(राजग) ने जंगलराज को रोका, वैसे ही बंगाल अब तुणमूल के महा-जंगलराज को विदा करने के लिए तैयार है।

मोदी ने अवैध घुसपैठ को बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि तुणमूल सरकार घुसपैठियों को खुली छूट दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुणमूल घुसपैठियों के समर्थन में धरने-प्रदर्शन तक करती है, क्योंकि वह उनके लिए वोट बैंक हैं और सरकार को देश तथा बंगाल की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। यह सरकार

घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने बंगाल के युवाओं से विशेष रूप से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी सूत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती।

मोदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा, बंगाल को करीब आधा दर्जन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं, जिनमें से तीन ट्रेनें आज ही शुरू की गई हैं। इनमें एक ट्रेन उनके संसदीय क्षेत्र काशी को बंगाल से जोड़ने वाली है और अन्य ट्रेनें दिल्ली और तमिलनाडु के लिए चलाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि शायद पिछले 100 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब 24 घंटे के भीतर बंगाल की रेल संरचना को लेकर इतने बड़े फैसले लिए गए हों।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोई नहीं चाहता, मुंबई में भाजपा का मेयर बने- राउत

मुंबई, 18 जनवरी। बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद मुंबई की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना-यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि शिंदे गुट ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के ताज

- संजय राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे ने 29 पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में बंधक बना रखा है।

होटल में बंधक बनाकर रखा है। राउत के इस बयान ने नगर निगम चुनाव के बाद मेयर पद की जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है।

संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतकर आए पार्षदों को होटल में कैद कर दिया गया है। राउत ने कहा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप के विरोध में ग्रीनलैंड व डेनमार्क में विशाल विरोध प्रदर्शन

कोपेनहेगन, 18 जनवरी। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के अमेरिकी प्रयासों और बयानों के विरोध में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के कई शहरों में विशाल विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं।

डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के सिटी हॉल स्क्वायर पर शनिवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे (भारतीय समयानुसार अपराह्न 4:30 बजे) भारी भीड़ जमा हुई, जिसने अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाला।

- ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हुए प्रदर्शन में प्रधानमंत्री निल्सन भी शामिल हुए।

इस प्रदर्शन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों देशों के नागरिक शामिल हुए, जो अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे।

इस बीच ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में भी दोपहर से ही लोग जुटना शुरू हो गए और "ग्रीनलैंडवासियों का है ग्रीनलैंड" के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक इटुइट गीत गाए और कई लोग "मैंक अमेरिका गो अवे" (अमेरिका को वापस भेजो) लिखी हुई टोपियों पहने नजर आये।

शिंदे ने मुम्बई के महापौर पद पर दावा किया , भाजपा नाराज़

चर्चा के अनुसार, यह विवाद कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में वर्चस्व से भी जुड़ा हुआ है

मुंबई, 18 जनवरी। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति गठबंधन के भीतर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा मुंबई महानगरपालिका के महापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष पद पर दावे किए जाने से भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है।

सूत्र बताते हैं कि भाजपा नेताओं का मानना ​​है कि मुंबई की जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है, लेकिन ऐसे समय में सहयोगी दल द्वारा दबाव की राजनीति अच्छे संकेत नहीं देती। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने अपनी यह नाराजगी सीधे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सामने रखी है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह पूरा विवाद केवल मुंबई के पदों की लड़ाई नहीं है, बल्कि कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी)

यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर रोक लगाई

अमेरिका द्वारा यूरोपीय यूनियन व डेनमार्क पर आयात शुल्क की घोषणा के बाद यह कदम उठाया गया

ब्रुसेल्स, 18 जनवरी। ग्रीनलैंड मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईयू ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी है।

ईयू ने यह कदम डेनमार्क और संघ के कई देशों पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद उठाया है। ईयू के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये आयात शुल्क संघ और अमेरिका के संबंधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। साथ ही, उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि जुलाई 2025 में प्रस्तावित समझौते को आयात शुल्क कम करने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था। हालाँकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के रुख और आयात शुल्क लगाने की उनकी चेतावनी के बाद संघ ने इस प्रस्तावित समझौते के अनुमोदन को रोकने का आा न किया है।

- ईयू के नेताओं ने डेनमार्क व ग्रीनलैंड को पूर्ण समर्थन दोहराते हुए कहा कि संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता ऐसे सिद्धांत हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

ट्रंप ने ग्रीनलैंड के रणनीतिक स्थान और खनिज संसाधनों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चेतावनी दी, "एक फरवरी 2026 से, उपर्युक्त सभी देशों द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। एक जून 2026 को यह शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह तब तक लागू रहेगा, जब तक ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं हो जाता।"

यूरोपियन पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष सिगफ्राइड मूरसन और अन्य यूरोपीय अधिकारियों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घोषणा उस स्थिरता को कमजोर करती है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए यह व्यापार समझौता किया गया था।

मूरसन ने कहा, "पिछले साल

अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच हुए व्यापार समझौते से स्थिरता ही एकमात्र लाभ होता। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई ईयू सदस्य देशों पर नए आयात लगाने की आज की घोषणा उस स्थिरता को छीन लेती है। यही कारण है कि उस व्यापार समझौते के अनुसमर्थन को स्थगित करना उचित है।"

मूरसन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमें पिछले जुलाई के ईयू-यूएस व्यापार समझौते को बहुत जल्द अनुमोदित करना था, जिससे अमेरिका से यूरोपीय संघ में होने वाले आयात पर आयात शुल्क शून्य हो जाता। हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए इस मंजूरी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।"

अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए डेनमार्क के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

त्रिवेणी में मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ ने डुबकी लगाई

प्रयागराज , 18 जनवरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर रविवार शाम पांच बजे तक चार करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा चुके थे। आज सुबह चार बजे से ही मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो गया था।

- सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया था तथा शाम 5 बजे तक चार करोड़ से अधिक लोग डुबकी लगा चुके थे।

जैसे-जैसे सूरज निकला उसी, रप्तार से श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ने लगी। भीड़ का आलम ये था कि 11 बजे सुबह तक ही एक करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी योजना में बदलाव करते हुए लोगों को दूसरे रास्ते से स्नान घाट तक पहुंचाया। मौसम ने भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने गाज़ा “बोर्ड ऑफ पीस” के लिए भारत को आमंत्रित किया

वॉशिंगटन, 18 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाज़ा में शांति बहाली के लिए बनाए जा रहे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गाज़ा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति

- यह बोर्ड गाज़ा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है।

प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है।

भारत को यह न्योता उसकी वैश्विक साक्ष, संतुलित विदेश नीति और शांति प्रयासों में भूमिका को देखते हुए दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बोर्ड में शामिल देश गाजा की स्थिति पर नजर रखेंगे, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और संघर्ष रोकने से जुड़े कदमों पर विचार करेंगे। हालाँकि, इस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत ऊर्जा साझेदारी है, जिसमें दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था शामिल है।

रही है।

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी भारत की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी, और पिछले एक दशक में यह उनकी भारत की पाँचवीं यात्रा होगी। यह यात्रा हाल ही में हुए उच्च-स्तरीय आदान- (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्णतया डॉलर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता भारत

इस पूर्ण निर्भरता का दुष्परिणाम भारत के सामने है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध ने रूस को विदेशी मुद्रा के रिज़र्व्स को ब्रेफ्रीज कर दिया था

- भारत ने डॉलर पर पूर्ण निर्भरता से बचने के लिए “ब्रिक्स ब्रिज” सिस्टम शुरू किया है। “ब्रिक्स ब्रिज” के मार्फत नए विकासशील देश, माल निर्यात-आयात का सेंटलमैंट अपनी स्वयं की मुद्रा से कर सकेंगे।

- यह नया “ब्रिक्स ब्रिज” सिस्टम भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत अपनी ऑयल की खपत का 80 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है तथा रूस से भी पुराने व मजबूत सामरिक संबंध रखता है। अतः यूरोपियन द्वारा सीधे रूस से ऑयल खरीद पर प्रतिबंध लगाने पर, भारत ने वैकल्पिक पैमेंट की व्यवस्था का इस्तेमाल किया।

- भारत यह “इम्पेशन” भी नहीं देना चाहता कि वह डॉलर विरोधी है, पर सारे निर्यात-आयात के लिए केवल एक “गेट कीपर” पर ही निर्भर रहना नहीं चाहता। इसलिए भारत “ब्रिक्स ब्रिज” सिस्टम को प्रोत्साहित कर रहा है। भारत यह जानता है कि “ब्रिक्स ब्रिज” सिस्टम पूर्णतया विकसित होने में काफी समय लगेगा, तब तक भारत डॉलर विरोधी होने की छवि भी नहीं ओढ़ना चाहता, जिससे वह अमेरिका का कोप-भाजन बने।

कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करता है। नई दिल्ली के लिए, इस प्रोजेक्ट का महत्व डॉलर को सीधे चुनौती देने

में नहीं है, बल्कि भविष्य में अलग-अलग रास्ते चुनने की रणनीतिक आजादी में है। यह एक समानांतर वित्तीय रास्ता बनाने के बारे में है, जिससे

भारत को ट्रेड, एनर्जी खरीद और क्रॉस-बॉर्डर भुगतानों में ज्यादा स्वायत्तता मिले, ऐसे समय में, जब जियोपॉलिटिक्स फाइनैस तक पहुंच को

तेजी से आकार दे रही है।

भारत कभी भी वैचारिक रूप से डॉलर का विरोधी नहीं रहा है। यू.ए. करंसी भारत के ट्रेड इनवॉइसिंग, फॉरेन

CMYK

●

●

●

●

⊕

●

●

●

⊕

●

●

●

●

⊕

●

●

●

●

CMYK